सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया है, परन्तु इन उद्योगों की गिरती हुई स्थिति की अनदेखा किया जाता रहा है।

अनेक क्षेत्रों में भारत सरकार के लघु उद्योग विकास आयुक्त ने बहुत सी योजनाएं इस सम्बन्ध में बनाई हैं और वे कार्यान्वित हो रही हैं। ऐसी ही एक योजना दिल्ली के उद्योग-धंधों को पनपाने के लिए अभी हाल ही में लागू हुई है। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में भी इसी तरह की योजना लागू की जाए।

इस क्षेत्र में उद्योगों के समक्ष सब से बड़ी कठिनाई तो विद्युत् की है। अन्य कठिनाइयों में कच्चे माल का न मिलना, समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता, मौजूदा प्रतिस्पर्धा का होना एवं इन उद्योगों द्वारा बनाई हुई चीजों के बेचने में कठिनाई आदि हैं। रेल सेवा का अभाव, टेलीफ़ोन व्यवस्था का सुचारू रूप से न चलना इन कठिनाइयों को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। ये व्यवस्थाएं शीघ्र ही इन उद्योगों के बचाव के लिए आवश्यक हैं। छोटे उद्योगों के घाटा उठाने की क्षमता अधिक नहीं होती। इस कारण वे शीघ्र ही बन्द हो जाते हैं। इससे जनता के छोटे तबकों को विशेषकर संकट हो जाता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस ओर तुरन्त कार्यवाही करें।

(x) DEMAND TO PRESCRIBE THE HISTORY TEXT BOOK FOR EIGHTH CLASS IN MAHARASHTRA

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Government has often expressed its serious concern and anxiety to ensure that text books are free from historical distorions and communal bias. Unfortunately, however, such text books still continue to get prescribed for study in our educational institutions. There is a strong feeling, anguish and resentment in Maharashtra against the history text book prescribed for Standard VIII as the matter contained under the Chapter "Islam Ka Uruj" in almost all languages, and especially in Marathi and Urdu, is highly erroneous, sacrilegious and provocative. There is public agitation against the text book. Other Chapter of this history text book are also replete with errors, distortions and irresponsible statements. At several places even dates given in the text book are so rediculously wrong that they create wide disparities to the extent of even two centuries.

I urge upon the Government the urgent necessity to proscribe and confiscate the said text book and to make a statement thereon in the House outlining how such text book came to be prescribed and steps taken to prevent such recurrences in future.

(xi) SUPPLY OF DRINKING WATER AND ELECTRICITY TO THE PEOPLE OF DINDIGUL, TAMIL NADU.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Tamil Nadu Government have had failed to give electricity supply to the pumpsets of the farmers for irrigation. The farmers in my Dindigul Parliamentary Constituency are facing an unprecedented crisis in the supply of electricity. The towns and villages also are not getting the electricity supply. The entire farm and the industrial productions are seriously affected. The drinking water is supplied to Dindigul towns and other towns of my constituency once in five days. The people are purchasing drinking water by paying 25 n.p. to Rs. 1.50 per pot in different towns of my constituency. The farmers are unable to save the standing crops neither they could raise new or fresh crops due to the failure of electricity supply. I resorted to hunger-strike on these demands a few months back at Dindigul town. But the authorities concerned woefully neglected to implement demands as I belong to the opposition DMK Party.

[Shri K. Mayathevar]

I therefore, request the Central Government, especially the Ministry of Electricity and Irrigation to instruct the Tamil Nadu Government to provide (i) the drinking water and (ii) the supply of electricty and Irrigation to instruct the Tamil Nadu Government to provide (i) the drinking water and (ii) the supply of electricity to all farmers and to all my Dindigul constituency people.

(xii) URGENT NEED TO INCREASE THE WAGES OF AGRICULTURAL LABOURERS TO IMPROVE THEIR ECONOMIC CONDITIONS.

श्री हरीश कुमार गंगावार (पीलीभीत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन देश के कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

देश के विभिन्न भागों में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी आज के महंगाई से त्रस्त समय में सब से कम है। देश के उन्नत व समृद्ध राज्य महाराष्ट्र के मजदूर को अधिकृत सूचना के अनुसार केवल 4 रुपये से साढ़े-पांच रुपये तथा उड़ीसा में 5 रुपये प्रतिदिन कृषि मजदूर को मजदूरी दी जाती है। कुछ अन्य राज्यों में मजदूरों की स्थिति इस से बेहतर नहीं है और असंगठित होने के कारण खेतिहर मजदूरों का शोषण जारी है।

कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के मामले में हरियाणा, पंजाब व केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ सब से आगे हैं, जहां न्यूनतम मजदूरी 14 रुपये प्रतिदिन है।

केन्द्रीय सरकार ने कुछ ही समय पूर्व केन्द्रीय क्षेत्रों के कृषि मजदूरों के लिए 6 रुपये 75 पैसे से 10 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी घोषित की थी। यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ये दरें राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं हैं तथापि कृषि के मामलों में उन राज्यों को जिन में मजदूरी दर 7 रुपये प्रतिदिन से कम है, सलाह दी गई थी कि वे न्यनतम मजदूरी छः रुपये पछत्तर पैसे प्रतिदिन निर्धारित करने के लिए कार्यवाही करें।

अगस्त, 81 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि न्यूनतम वेतन गरीबी की रेखा के नीचे न जाये, न्यूनतम वेतन का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बन्ध जोड़ने का तरीका निकाला जाय लेकिन महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा अन्य कुछ राज्यों में खेतिहर, मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी मिल रही है उस से इस निर्णय से कोई लाभ नहीं पहुंचा, ऐसा लगता है।

भारत के 5 करोड़ 40 लाख खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा सुधार कर उन्हें कम से कम भरपेट रोटी देने के लिए उन के असंगठित होने के कारण शोषण से बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार को तुरन्त करना चाहिए।

(xiii) ARTIFICIAL SHORTAGE OF SODA ASH.

SHRI RATANSINH RAJDA: Cyclic artificial shortage of soda ash has become a regular feature, creating untold hardships for small scale industries and consumers like washermen. Innumerable small-scale industries are destablised on account of spiralling prices of each ash.

Soda ash is produced by four monopoly producers, who have absolute control over production, distribution and pricing, in the absence of any statutory control. The usual plea of cost escalation at the root cause of price increase is not convincing at all. From the minute study of balance-sheets of producers, it is clear that the cost of one tonne soda ash should not be more than Rs. 700 to Rs. 800/-. Unfortunately, black market has already reappeared. Market prices have soared from Rs. 2,000 to Rs. 2,800 per tonne. Conditions have to be created so that producers reduce their prices consistent with the cost of production. The following